प्रभातखबर

'' नई झाड़ू भले ही बेहतर सफाई कर सकती हो, लेकिन पुरानी झाड़ू की पहुंच कोने-कोने तक रहती है।''

परिवार और पसंद का फर्क!

किसी हद तक भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने ठीक ही कहा है कि मेरा समय पूरा हो जाने पर कोई बता सकता है कि अगला अध्यक्ष कौन होगा...? क्या ऐसा अन्य दल कह सकते हैं? सही है कि सवा सौ साल से ज्यादा पुरानी कांग्रेस में तो ऐसी परिपाटी नहीं है कि गांधी-नेहरू परिवार से बाहर का कोई अध्यक्ष बन सके... और अगर कोई बना भी है तो इस परिवार के आशीर्वाद से ही! तो कांग्रेस से ऐसी उम्मीद नहीं है। मुलायमसिंह ने बेटे को ही आगे बढ़ाया तो लालू यादव का तो कुनबा ही इतना सम्पन्न है कि कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। करुणानिधि के रहते किसी और के बारे में सोचना भी पाप है और मायावती, ममता भी अपने परिवार के भरोसे ही राजनीति चला रही हैं और खुद ही मुखिया हैं। शिवसेना पर ठाकरे की मुहर जरूरी है तो वायएसआर कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस और तमाम बची हुए कांग्रेस या अजीतसिंह का दल अकेले परिवार के दम पर है। ले-देकर नीतीश कुमार ही हैं। जनता दल (यू) में परिवार इसलिए नहीं है कि मुख्यमंत्री का इंजीनियर बेटा इधर कोई दिलचस्पी ही नहीं ले रहा है। हां, वामपंथी दल हैं, जहां परिवारवाद नहीं है, लेकिन वहां भी कौन मुखिया बन रहा है, यह पहले से पता लग जाता है! इस लिहाज से भाजपा का मामला अनूठा है कि चुनाव हारने के बाद तीसरी बार अध्यक्ष बने आडवाणी को हटाकर नागपुर-पुत्र नितिन गडकरी को ऐसे बैठाया कि किसी को सम्पट ही नहीं बैठी। फिर अमित शाह को भी ऐसे ही लाया गया, लेकिन तब तक संघ से ऊपर नरेंद्र मोदी हो चुके थे।

यह बताना मुश्किल है कि भाजपा का अगला अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन यह तो कहा ही जा सकता है कि संघ और नरेंद्र मोदी की पसंद से ही नया नाम तय होगा! तो क्या भाजपा इसलिए ही अन्य दलों से अलग और महान है कि शाह के बेटे को अध्यक्ष नहीं बनाया गया? क्या चार (या दो?) लोग माथा जोड़कर बैठ जाएं और किसी नाम पर सहमति हो जाए, क्या यही लोकतांत्रिक दल होने का सबूत है? परिवार से किसी को कुर्सी पर बैठा देना और अपनी पसंद को पद दे देना क्या अलग-अलग है? यदि भाजपा अपने को अलग और लोकतांत्रिक दल बताने के लिए इतनी ही उधार है तो फिर अध्यक्ष थोपने की कसरत बंद क्यों नहीं कर दी जाती? अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए और उसमें जो भी जीतकर आए, उसे ही पद देना चाहिए, नियम तो ऐसा ही है..., तो फिर यह भी तानाशाही नहीं है कि संघ और मोदी के इशारे पर कोई अध्यक्ष बना दिया जाए? परिवार से अध्यक्ष बनाना और पसंद के शख्स को कुर्सी देना क्या एक जैसी ही हरकत नहीं है? लोकतंत्र का खेल अपने बनाए नियम से नहीं चलता है और जब नियम अपने हिसाब से बदल दिए जाते हैं तो लोकतंत्र की आत्मा छटपटाने लगती है!

चमकदार नाम क्यों चाहिए... आस्कर को!

पश्चिम की आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है। उसके लिए बॉलीवुड के बाहर देख पाना अब भी बहुत मुश्किल है। हिंदी सिनेमा से अलग और भी बहुत कुछ है, लेकिन अकादमी के लिए इसे समझना तब तक मुश्किल है, जब तक कि वह अपनी आंखों पर पट्टी नहीं खोलता। ऐसा नहीं है कि अकादमी पूरी तरह इसे समझ पाने में नाकाम है, लेकिन भारतीय सिनेमा की विविधता को समझना अभी तक टेढ़ी खीर है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और असम का सिनेमा अभी तक अकादमी की निगाह से दूर है। फिर भी ये सच है कि अकादमी मुंबई जहां बॉलीवुड का दिल धड़कता है, वहीं तक देखती है।

अकादमी के अधिकांश लोग बॉलीवुड से ही जुड़े हैं। जिस अकादमी ने आस्कर वोटिंग क्लब में आठ हजार लोगों को बुलावा भेजा है, उसमें 774 ऐसे भारतीय लोग भी हैं, जो विंध्य से दक्षिण भारत तक अपने काम से जाने जाते हैं। नहीं तो इन लोगों को अकादमी का बुलावा नहीं आता। हॉलीवुड के रिपोर्टर स्काट फिनबर्ग ने कहा था कि अकादमी कभी विविधता को समझ नहीं पाई है। न ही इसका कोई हल है। यह वैसा ही है जैसे किसी कुत्ते को पूंछ से कुचलना...। अकादमी बुरी तरह से नाकाम है। मैं भी फिनबर्ग की इस बात से सहमत हूं। हालांकि, फिनबर्ग ने यह बात काले-गोरे लोगों के संबंध में कही थी। अकादमी भारत की समृद्ध और विशाल विविधता को समझने में कंजूसी कर रही है। 774 लोगों की सूची में इरफान, आमिर खान, आनंद पटवर्धन और बुद्धदेव दास गुप्ता (जो बंगाल से हैं) जैसों को शामिल किया है। मृणाल सेन के लीक से हट कर सिनेमा को अनदेखा किया गया है, वहीं 1969 में भुवन सोम (जिन्होंने नई धारा की शुरुआत की थी) जिन्होंने लंबे समय से कोई फिल्म नहीं बनाई। वे इन दिनों बीमार हैं। क्या वे वोटिंग सदस्य के रूप में अपनी भूमिका से न्याय कर पाएंगे? सूची में ही शामिल गौतम घोष का योगदान क्या है? अस्सी-नब्बे के दशक में 'पार', 'अंतर्जलि यात्रा' और 'पद्मा नाजिर माझी' जैसी फिल्मों के बाद उन्होंने औसत ही काम किया है।

ऐश्वर्य राय को भी उनके ग्लैमर की वजह से सूची में जगह मिली है। उनके पास कान फेस्टिवल में रेड कॉरपेट पर चलने के अलावा और कुछ काम नहीं है, जो अकादमी ने उन्हें बुलावा दिया। अकादमी को यूं भी ग्लैमर की जरूरत नहीं है। उन्हें उन लोगों की जरूरत है, जिनकी फिल्में अच्छा करने की काबिलियत रखती हैं। ऐश्वर्य की तरह ग्लैमर का दिखावा करने के लिए दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा काफी हैं, जो महान कलाकार नहीं हैं। इनकी तुलना रेखा, वहीदा रहमान और मीनाकुमारी से नहीं की जा सकती। एक-दो हॉलीवुड फिल्मों में दिख जाने के बाद नाम के लिए ये सब कर रही हैं। इन लोगों के चलते अडूर गोपाल कृष्णन और गिरीश कसरावल्ली जैसों की अनदेखी हो गई है। अकादमी का जो काम इन्हें करना था वो कोई और करेगा। मणिरत्नम और वेत्री रमण जैसे लोगों की सूची में शामिल होने से खुश होता। ऐसे और भी लोग थे, जो अकादमी में शामिल लोगों की तुलना में अपने काम से खास हैं। उनकी ओर देखा तक नहीं गया। अडूर को ही देख लो, जिनकी फिल्म 'पिनयूम' बहुत खास ही नहीं है, बल्कि साहसी प्रयास है, जिसे क्लासिक शैली में बना कर उन्होंने केरल की सामंती व्यवस्था पर अच्छी कहानी गढ़ी है। केरल के नायर समुदाय को भी उन्होंने इस फिल्म के जरिये उनकी रूढ़िवादिता को निशाना बनाया था।

अकादमी के अधिकांश लोग बॉलीवुड से ही जुड़े हैं। जिस अकादमी ने आस्कर वोटिंग क्लब में आठ हजार लोगों को बुलावा भेजा है, उसमे लगभग पौने आठ सौ ऐसे भारतीय भी हैं, जो विंध्य से दक्षिण भारत तक अपने काम से जाने जाते हैं। नहीं तो इन लोगों को अकादमी का बुलावा नहीं आता। हॉलीवुड के रिपोर्टर स्काट फिनबर्ग ने कहा था कि अकादमी कभी विविधता को समझ नहीं पाई है। यह वैसा ही है जैसे किसी कुत्ते को पूंछ से कुचलना...। अकादमी बुरी तरह से नाकाम है। उन्हें उन लोगों की जरूरत है, जिनकी फिल्में अच्छा करने की काबिलियत रखती हैं। ऐश्वर्य की तरह ग्लैमर का दिखावा करने के लिए दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा काफी हैं। इनकी तुलना रेखा, वहीदा रहमान और मीनाकुमारी से नहीं की जा सकती।

❑ चेन्नै से गौतमन भास्करन

'पिनयूम' में हम देखते हैं कि कैसे एक मामूली देवतावादी मंदिर में घूमते हुए गलत बातों का विरोध करता है और हत्या करने से रोकता है। दूसरे अतिवादियों को चुनौती देता है। इन सब में कैसे मन की खुशी मिलती है और इन छोटी-छोटी खुशियों में अस्तित्व तलाशा है, यह देखना बहुत सुखद है। अंत में जब नायक कई साल बाद अपनी पत्नी से मिलता है, तो वह पूछती है कि क्या हमारा जीवन अब भी अच्छा हो सकता है। क्या हम फिर से जी सकते हैं। ऐसे दृश्य फिल्माना हर किसी के बस में नहीं।

वहीं कसरावल्ली ने भी ऐतिहासिक फिल्मों 'घट श्राद्ध', 'तबराना कथे' (तबराना की कथा) और 'गुलाबी टॉकीज' के अलावा 'कुर्मावतार' (कछुआ) जैसी बहुत सी अच्छी फिल्में बनाई हैं। एक फिल्म में सरकारी नौकर की कहानी है, जो रिटायर होने वाला है। उसकी जिंदगी के हिस्सों पर अच्छी फिल्म है। फिल्म में महात्मा गांधी और उनके सिद्धांतों को लेकर उसकी जिंदगी को जोड़ा गया है।

'नयन' और 'रोजा' जैसी फिल्में बना कर मणिरत्नम ने अलग पहचान बनाई है। 'अलैयापुत' और 'कढल कानमनी' भी उनकी खास फिल्में हैं। कमल हासन भी शानदार अभिनेता हैं, जो विश्व सिनेमा के अच्छे जानकार भी हैं। ऐसे लोगों को अकादमी की सूची में होना था। तमिल सुपर स्टार रजनीकांत भी बेहतर कलाकार हैं। के. बालाचंदर और महेंद्रन के साथ अपने काम को याद करते हैं। अब वे शोमैन बन गए हैं। अपने चाहने वालों को खुश करने के लिए वे कुछ और ही नया करते रहते हैं। मैं मानता हूं कि चाहने वालों का आधार एक बात है, लेकिन अमिताभ बच्चन भी इसमें पीछे नहीं हैं। हो सकता है कि इन प्रशंसकों को भारत की संघर्षों से भरी जीवन शैली में उन जैसे अवतारों और फंतासी से भरे किरदारों की जरूरत है।

यदि अडूर, कसरावल्ली, मणिरत्नम, कमल हासन और वेत्री रमण जैसे लोगों को पसंद किया जाता है तो अच्छा होता, लेकिन प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्य और दीपिका जैसों को आस्कर में शामिल होना है। ऐसे में जरूरत है कि अकादमी अपना घर फिर से दुरुस्त करें और हां, अपना चश्मा बदल दे! ⓪

■ लक्ष्मीकांता चावला

जोखिम में बचपन

हमारे देश के सभी प्रांतों की सरकारें, बच्चों के भविष्य, उनके पोषण और शिक्षा के लिए कितनी गंभीर हैं, इसका नमूना है देश के इकतीस फीसदी स्कूलों में शौचालय नहीं हैं। जो दोपहर का भोजन दिया जाता है, वह भी इस योग्य नहीं कि माननीयों के बच्चे उस भोजन को खा सकें। कुछ बड़े शहरों के सरकारी स्कूलों को छोड़कर अधिकतर स्कूल भवनों की हालत खस्ता है, लेकिन गरीब का बच्चा जैसे-तैसे चार अक्षर सीखने इन स्कूलों में पहुंचता है।

मुझे कुछ समय पहले टीवी चैनलों पर वह स्कूल भी देखने को मिला, जहां पहुंचने के लिए बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश है कि पंजाब के सभी स्कूलों में जो कमरे लोक निर्माण विभाग ने खतरनाक बताए हैं, उन्हें जल्द गिरा दिया जाए। अब वैसी ही अफरा-तफरी में काम शुरू हो गया, जैसा नशे की रोकथाम के लिए सरकार ने शुरू किया था। स्कूलों के प्रबंधक, प्रधानाध्यापक, जिला शिक्षा अधिकारी इस चिंता में हैं कि नए कमरे बनाना तो दूर, पुराने कमरे गिराने के लिए धन कहां से और कैसे किया जाए और गरमी और बारिश से बचाने के लिए बच्चों को कहां बिठाकर पढ़ाया जाए।

सवाल है कि जो कमरे अब गिराने का आदेश अदालत ने दिया, क्या वे एक ही दिन में खतरनाक हो गए। सालों तक बच्चों की जान जोखिम में डाल कर उन्हें वहां क्यों बिठाया गया? जानकारी के मुताबिक जालंधर, नवां शहर, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला और तरनतारन जैसे कई जिलों में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, जिनकी इमारतें कमजोर हैं। उनमें अध्यापक और बच्चे मौत के साए में पढ़ने-पढ़ाने को विवश हैं। सवाल है कि अगर सालों पहले ही पंजाब का लोक निर्माण विभाग इन भवनों को खतरनाक मानचुका था, तो अब तक इन्हें गिराया क्यों नहीं गया और नए भवन क्यों नहीं बनाए गए? ऐसा शायद इसलिए किया गया होगा कि इन स्कूलों में न तो सरकार और सरकारी अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं और न उन्होंने कभी इन स्कूलों की हालत को नजदीक से देखा है।

अमृतसर में केवल उन्नीस साल पहले करोड़ों रुपए की लागत से बने सर्किट हाउस के शानदार और सब तरह की सुविधाओं से सुसज्जित कमरों को गिराने का काम पंजाब सरकार ने शुरू कर दिया है। शायद नए सर्किट हाउस को वे पांच सितारा सुविधाओं से लैस बनाना चाहते हैं, लेकिन जो सरकारी स्कूलों के भवन बच्चों के बैठने के लिए खतरनाक मान लिए गए, उन्हें बनाने की न तो सरकार को चिंता है और न उसके लिए अनुदान मिलने की उम्मीद दिख रही है, लेकिन अगर सचमुच सरकार धन के अभाव के कारण नए भवन नहीं बनवा सकी, तो कितना अच्छा होता कि कम से कम दो साल के लिए सभी सांसदों और विधायकों, मुख्य संसदीय सचिवों को यह निर्देश दे दिया जाता कि वे अपनी निधि का सदुपयोग केवल अपने-अपने क्षेत्र के स्कूलों के भवनों की स्थिति सुधारने में करें। इससे हमारे गरीब विद्यार्थी सुविधाजनक सुखद माहौल में शिक्षा भी लेते और जीवन का खतरा भी सामने न रहता।

मुझे हैरानी होती है कि जिस देश के इकतीस फीसदी स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं, उस देश के राजनेता वोट लेने के लिए कभी विद्यार्थियों को लैपटॉप या साइकल बांटते हैं, तो कभी स्कूटी दिलाने का भरोसा देते हैं। इसी देश में विद्यार्थी खतरनाक भवनों में पढ़ने को मजबूर हैं। इन स्कूलों में अध्यापकों की कमी भी बहुत बड़ी समस्या है। जब कोई विधायक या सांसद त्यागपत्र दे देता है या उसकी मौत हो जाती है तो उसकी सीट छह महीने के अंदर ही भर ली जाए, यह व्यवस्था है, पर अध्यापकों के पद सालों तक खाली पड़े रहें तो भी सरकारें भर्ती करने का आदेश नहीं देतीं।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खतरनाक कमरे गिराने का आदेश तो दे दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट से ही यह प्रार्थना करनी होगी कि नए कमरे बनवाने का आदेश भी वही जारी करे, अन्यथा सरकार नए होटल, सर्किट हाउस तो अपनी सुविधा के लिए बना लेगी, पर स्कूलों के भवन तभी बनेंगे, जब कोर्ट आदेश देगा, लेकिन सच यह भी है कि कोर्ट के आदेश मानने में भी हमारी सरकारें बहानेबाजी करती हैं। ठीक उसी तरह, जैसे न्यायालय के आदेश के बावजूद राष्ट्रीय राजमार्गों से शराब के ठेके खत्म नहीं किए गए। कहीं-कहीं कानून को भ्रम में डालने के लिए ठेके का दरवाजा सड़क के दूसरी ओर निकाल लिया है। ⓪

न्याय की मिसाल

उन दिनों अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे एक व्यक्ति ने जेल में दस साल शांति और प्रेम से बिताने के बाद शेष सजा माफ किए जाने का प्रार्थना-पत्र राष्ट्रपति लिंकन के पास भेजा। प्रार्थना-पत्र के साथ उन दिनों किसी खास व्यक्ति या कैदी के किसी जिम्मेदार संबंधी का संस्तुति-पत्र नत्थी किया जाना जरूरी होता था। ऐसा न करने पर कैदी की माफी की अपील पर विचार ही नहीं होता था। कैदी ने प्रार्थना-पत्र में अपनी योग्यता, प्रतिभा और काम का ब्यौरा तो भेजा, लेकिन कोई संस्तुति पत्र वह नत्थी न कर पाया। उसे पढ़कर लिंकन बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने कैदी की सजा माफ किए जाने पर गंभीरता से विचार किया, लेकिन उनके कानूनी सलाहकार ने कहा - 'सर, इस कैदी के प्रार्थना-पत्र के साथ किसी खास व्यक्ति या संबंधी का संस्तुति-पत्र तो संलग्न ही नहीं है। नियमों के अनुसार इसकी सजा माफ किए जाने पर विचार नहीं किया जा सकता।

यह सुन लिंकन ने कैदी की सचाई के बारे में पता लगाया। मालूम हुआ कि वह कैदी वास्तव में सुधर गया था और जिम्मेदार नागरिक बनने की कोशिश में था। लिंकन ने सोचा कि अगर उसके पत्र पर विचार नहीं किया तो न्याय के लिए गलत संदेश जाएगा। अधिकारियों के अलावा साथी कैदियों ने भी हामी भरी। यह जानकर लिंकन ने कानूनी सलाहकार से कहा - भले ही कोई सिफारिशी नहीं है, लेकिन वह वाकई इस काबिल हैं कि शेष सजा माफ कर उसे आम जीवन बिताने का मौका मिले। मैं उसका संस्तुति पत्र लिखता हूं। उन्होंने उसका प्रार्थना-पत्र ले लिया। कैदी को पता चला तो वह न्याय की इस मिसाल के लिए श्रद्धा से भर उठा। ⓪

किसी हमले से नहीं झुकता भारत!

नईदुनिया में नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कायराना हमले के आगे झुकेंगे नहीं। वैसे वो आसानी से बोलते नहीं हैं, पर इसके बाद तो बोलना ही था। **दैनिक भास्कर** लिख रहा है कि कुछ ही दूरी पर इंदौर के यात्रियों की बस भी थी। जीप से बांधकर जिस फारुक अहमद डार को घुमाया गया था, उन्हें दस लाख रुपए देने को कहा गया है। मानव अधिकार आयोग ने राज्य सरकार से ऐसा कहा है और इस खबर को **नईदुनिया** ने भी पहले पन्ने पर लगाया है। **पत्रिका** में मोदी कह रहे हैं भारत नहीं झुकेगा, पर इस तरह के बयान की जरूरत ही क्या है। क्या इन हमलों से भारत झुक सकता है? नीचे खबर है कि उत्तरप्रदेश का संदीप तो लश्कर का आदिल बन गया था और उस पर सेना के साथ पुलिस पर भी हमले के इलजाम हैं। अब अंदर वाला हेडिंग देखिए - **मानव ढाल बने पत्थरबाज को दस लाख रुपए का मुआवजा।** हद है, जब मानव अधिकार आयोग कह रहा है कि गलत आदमी को जीप से बांध दिया गया था, ये अच्छा अमल नहीं है तो भी उसे यहां पत्थरबाज लिखा जा रहा है।

राज एक्सप्रेस ने पहले पन्ने के तले में खबर छापी है कि अमेरिका से कच्चे तेल की सप्लाई शुरू हो गई है और इस खबर में मोदी-ट्रम्प का गले मिलते फोटो भी है। अब इसमें इस फोटो की क्या जरूरत है। बरसों से तिजारत की जा रही है और ये सब तो होता रहा है, लेकिन अभी तो जो भी होगा, मोदी के खाते में जाएगा। लालूप्रसाद यादव के बेटे के इस्तीफे की जो बात चल रही है, उससे तो उनकी पार्टी ने इंकार कर दिया है। अब गेंद नीतीश कुमार के पाले में है, जो आजकल में फैसला कर सकते हैं। राहुल गांधी ने चीनी राजदूत से मुलाकात की तो हंगामा मच गया और इस हंगामे की कुछ वजह तो कांग्रेस भी है, जो एक बात नहीं कर पाई। पहले कुछ बोली, बाद में कहती पाई गई कि नरेंद्र मोदी अगर चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं तो फिर राहुल क्यों नहीं। **पीपुल्स समाचार** ने इस खबर को पहले पन्ने पर लगाया है। आखिर पन्ने पर खबर है कि आज उपराष्ट्रपति के लिए जो विपक्ष साथ बैठने वाला है, उसमें नीतीश कुमार नहीं जाएंगे, पर शरद यादव जाएंगे, यानी खेल जारी है।

सरकारी जांच से क्या उम्मीद की जा सकती है। ये ऐसा मीटर है, जो वही बताता है, जो सरकार चाहती है। अखलाक के फ्रिज से वही निकाला जाता है, जो निकालना रहता है। ऐसे में बड़े अस्पताल का आक्सीजन सप्लाय कैसे बिगड़ा हुआ निकल सकता था। उसे तो सुधरा हुआ ही निकलना था और **नईदुनिया** के पेज तीन पर खबर है कि सत्रह मौत के मामले में जो रपट आई है, उससे पता चल रहा है कि आक्सीजन सप्लाई बंद नहीं हुई थी। इस पन्ने की पहली खबर बारिश है, जिस पर नई तारीख मिली है। चार दिन बाद बारिश आ सकती है, ऐसी उम्मीद जताई गई है और बादलों से सिर्फ उम्मीद ही की जा सकती है। सूखे में ही ओम नमः शिवाय गूंज गया और मंदिरों में अच्छी बारिश की दुआ भी हो गई, जिसका जिक्र **दैनिक भास्कर** मजहबी पन्ने पर किया है।

पहले पन्ने पर विकासिंह राठौर की खबर बता रही है कि इंदौर एयरपोर्ट पर भी हाथ वाले बैग में टैग नहीं लगाना पड़ेगा। वैसे खबर एयरइंडिया के इकानॉमी क्लास की भी है कि नॉनवेज पर पाबंदी लगा दी है और वजह खर्चा बताया गया है, यानी जो बिजनेस क्लास में घूम रहे हैं, उन्हें सब तरह का खाना दिया जाएगा और यहां भी दो हिस्से तो हो ही गए हैं। वैसे जारी रखा जा सकता था, इतना घाटा तो नहीं होता, क्योंकि इस मौसम में हर तरह का नॉनवेज सस्ता हो जाता है।

सिटी फ्रंट पेज पर गुंडा-मुहिम है। पचास से ज्यादा गुंडों के कब्जों को निशानदेह कर लिया गया है। **पत्रिका** के पेज तीन से पता चल रहा है कि होलकर साइंस कॉलेज में यूजी की 46 फीसद सीटें खाली हैं और यहां भी गुंडों के कब्जों का जिक्र है, जिन्हें बस तोड़ने की तैयारी हो गई है और गुंडे चेतन से इसकी शुरुआत हो रही है। **दबंग दुनिया** के पहले पन्ने पर भी चेतन दिखाई दे रहा है, जिसकी मदद पुलिस वाला कर रहा था। कॉल डिटेल में उसका नाम आया है। हालांकि एएसपी रूपेश द्विवेदी को इसकी कोई जानकारी नहीं है। आतंकी हमले को तो यहां बड़ी जगह मिली है, लेकिन जमीन के बिना तो पन्ना पूरा होता नहीं है। सांई प्राइम बिल्डकॉन का जिक्र किया गया है और अंदर भी जमीन है। चरनोई की जमीन पर मकान और स्कूल बना दिया गया है, यानी कहां, किस जमीन पर क्या बन रहा है, जानने के लिए यहां की तफरीह की जा सकती है।

पीपुल्स समाचार के पहले पन्ने पर उदापुरा से खबर है, जहां बेटी की लाश गोद में लेकर मां-बाप बाजार से गुजर गए, क्योंकि एम्बुलेंस ने तो गांव तक छोड़ने से इंकार कर दिया था। इस तरह की खबरें अब खूब छपने लगी हैं। जो आतंकी हमला हुआ है, वो यहां नीचे है और ज्यादा फैलाकर छापा भी नहीं गया है। अंदर कुछ खास नहीं है और विचारवान पन्ना भी बिना कुछ दिए ही पूरा हो रहा है। दबंग दुनिया के देश-विदेश वाले पन्ने पर नवाज शरीफ का भ्रष्टाचार है। पनामा पेपर्स के बाद से ही

इस तरह की खबर आने लगी हैं और उन पर मुकदमा दर्ज करने की बात भी की जा रही है। वैसे भी शरीफ के लिए आगे का सफर आसान नहीं है और फिर पाकिस्तान में कब, क्या हो जाए कह नहीं सकते। **दैनिक भास्कर** में शेखर गुप्ता का लेख है, जिसे पढ़ा जा सकता है और खेल पन्ने पर कोच की कशमकश है, जिसे गांगुली ने ये कहकर आराम दे दिया है कि जब विश्व कप के लिए ही कोच चुनना है तो जल्दी क्या है। ये बात पहले भी कह सकते थे, इतना तमाशा तो नहीं होता, पर तमाशा नहीं होता तो इधर नजर कैसे जाती, इसलिए तमाशा तो चलता रहेगा।

❑ नाबीना (nabina731@gmail.com)

वाह-वाह

मैं बहुत कम किसी से मिलता हूं,
जिससे यारी है, उससे यारी है,
हम जिसे जी रहे हैं वो लम्हा,
हर गुजिश्ता सदी पे भारी है।

❑ अख्तर नज्मी